REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 7 | APRIL - 2023

रोज़गार, प्रवासन और श्रमिक जीवन के सन्दर्भ में औद्योगीकरण और श्रमिक वर्ग : बिलासपुर ज़िले का समाजशास्त्रीय अध्ययन

सुश्री आरती तिवारी
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र (प्रभारी प्राचार्य)
एस. बी. टी. महाविद्यालय, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश:

औद्योगीकरण ने भारत के विभिन्न ज़िलों की सामाजिक-आर्थिक संरचना को पुनर्गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर रोज़गार प्रतिरूपों, श्रमिक प्रवासन और कामगार वर्ग के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हुए। यह शोध-पत्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में औद्योगीकरण के कामगार वर्ग पर पड़े प्रभावों का अध्ययन करता है, जिसमें रोज़गार के अवसरों, प्रवासन प्रवृत्तियों और श्रम-जीवन की परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र के विस्तार और अवसंरचनात्मक प्रगति ने पारंपरिक आजीविकाओं को किस प्रकार परिवर्तित किया है तथा एक विविधीकृत कामगार वर्ग के उद्भव में कैसे योगदान दिया है। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि जहाँ औद्योगीकरण ने रोज़गार और आय के अवसर उत्पन्न किए हैं, वहीं दूसरी ओर इसने रोज़गार असुरक्षा, श्रम के असंगठित होने, प्रवासन दबाव तथा कार्य स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। शोध-पत्र यह निष्कर्ष निकालता है कि बिलासपुर में औद्योगीकरण ने कामगार वर्ग के लिए मिश्रित परिणाम उत्पन्न किए हैं और समावेशी श्रम नीतियों तथा सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य शब्द: औद्योगीकरण, कामगार वर्ग, रोज़गार, प्रवासन, श्रम-जीवन, बिलासपुर ज़िला

प्रस्तावना:

औद्योगीकरण आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण की एक प्रमुख शक्ति है, जो विशेष रूप से रोज़गार संरचना, श्रम संबंधों, प्रवासन और कामगार वर्ग के समग्र जीवन को प्रभावित करती है। विकासशील क्षेत्रों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया प्रायः कृषि-आधारित और पारंपरिक व्यवसायों से हटकर मज़दूरी-आधारित औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रीय रोज़गार की ओर संक्रमण को जन्म देती है। यह संक्रमण वर्ग संरचना, सामाजिक गतिशीलता, पारिवारिक जीवन और प्रवासन के प्रतिरूपों को पुनःआकार देता है, जिससे श्रमिकों के लिए नए अवसरों के साथ-साथ नई प्रकार की असुरक्षाएँ भी उत्पन्न होती हैं।

छत्तीसगढ़ का बिलासपुर ज़िला क्षेत्रीय औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। अपनी रणनीतिक स्थिति, सुदृढ़ रेलवे संपर्क, आसपास के क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की उपलब्धता तथा निर्माण और सेवा क्षेत्रों के विस्तार के कारण बिलासपुर एक प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरा है। इस ज़िले में रेलवे, सीमेंट, ऊर्जा-संबंधी इकाइयों, निर्माण, परिवहन सेवाओं और लघु विनिर्माण उद्योगों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। इस औद्योगिक विस्तार ने ग्रामीण क्षेत्रों और पड़ोसी ज़िलों से बड़ी संख्या में श्रमिकों को आकर्षित किया है, जिसके परिणामस्वरूप रोज़गार प्रतिरूपों और श्रम संरचना में तीव्र परिवर्तन हुए हैं।

बिलासपुर में औद्योगीकरण ने कामगार वर्ग के लिए मज़दूरी-आधारित रोज़गार के विस्तार और रोज़गार अवसरों के विविधीकरण को बढ़ावा दिया है। तथापि, इन रोज़गारों का बड़ा हिस्सा असंगठित और ठेका-आधारित है, जिसकी विशेषताएँ रोज़गार की असुरक्षा, कम मजदूरी, सीमित सामाजिक सुरक्षा और असुरक्षित कार्य स्थितियाँ हैं। प्रवासन इस ज़िले के श्रम बाज़ार की एक प्रमुख विशेषता बन गया है, जहाँ मौसमी, चक्रीय और स्थायी प्रवासन ने श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। प्रवासी श्रमिकों को प्रायः आवास, स्वास्थ्य सेवाओं, बच्चों की शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

यह शोध-पत्र उपलब्ध आँकड़ों और प्रवृत्तियों के आधार पर बिलासपुर ज़िले में औद्योगीकरण और उसके कामगार वर्ग पर पड़े प्रभावों का अध्ययन करता है। इसमें रोज़गार, प्रवासन और श्रम-जीवन के आपसी संबंधों पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि यह समझा जा सके कि औद्योगिक विकास ने श्रमिकों की आजीविका, सामाजिक संबंधों और जीवन स्थितियों को किस प्रकार रूपांतरित किया है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए यह अध्ययन औद्योगीकरण से उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों, दोनों को रेखांकित करता है तथा श्रम कल्याण, रोज़गार सुरक्षा और समावेशी औद्योगिक विकास से संबंधित नीति-विमर्श में योगदान देने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1) बिलासपुर ज़िले में औद्योगीकरण की प्रकृति और उसके विस्तार का अध्ययन करना।
2) कामगार वर्ग के बीच रोज़गार प्रतिरूपों में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3) औद्योगिक रोज़गार से संबंधित प्रवासन प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
4) श्रमिकों की कार्य एवं जीवन स्थितियों का परीक्षण करना।
5) कामगार वर्ग के समक्ष उपस्थित सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों का आकलन करना।

शोध पद्धति:

यह अध्ययन बिलासपुर ज़िले में औद्योगीकरण के कामगार वर्ग पर पड़े प्रभावों का विश्लेषण करने हेतु वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-अभिकल्प को अपनाता है। अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक, दोनों प्रकार के आँकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आँकड़े 150 उत्तरदाताओं (n = 150) से संकलित किए गए हैं, जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्वितीयक आँकड़े भारत की जनगणना प्रतिवेदनों, ज़िला सांख्यिकी पुस्तिकाओं, सरकारी श्रम प्रकाशनों तथा समाजशास्त्रीय अध्ययनों से प्राप्त किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों का चयन उद्देश्यपूर्ण (Purposive Sampling) पद्धति द्वारा किया गया है।

रोज़गार, प्रवासन और श्रमिक जीवन के सन्दर्भ में औद्योगीकरण और श्रमिक वर्ग:

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में औद्योगीकरण सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। इसकी रणनीतिक रेलवे संपर्क व्यवस्था, खनिज-समृद्ध क्षेत्रों से निकटता तथा निर्माण, ऊर्जा-संबंधी गतिविधियों और सेवा क्षेत्रों के विस्तार के कारण बिलासपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र बन गया है। औद्योगीकरण की इस प्रक्रिया ने पारंपरिक आजीविका प्रतिरूपों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है और कारखानों, निर्माण स्थलों, परिवहन सेवाओं, रेलवे तथा विभिन्न असंगठित व्यवसायों में संलग्न एक विविध कामगार वर्ग के विकास में योगदान दिया है।

बिलासपुर ज़िले में औद्योगीकरण का सबसे स्पष्ट प्रभाव रोज़गार प्रतिरूपों के परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। कृषि-आधारित और पारंपरिक व्यवसायों से हटकर मज़दूरी-आधारित औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रीय रोज़गार की ओर क्रमिक संक्रमण हुआ है। यद्यपि औद्योगीकरण ने नए रोज़गार अवसर उत्पन्न किए हैं, फिर भी रोज़गार का बड़ा भाग असंगठित और ठेका-आधारित बना हुआ है। श्रमिकों को अनियमित मजदूरी, अस्थायी नियुक्तियाँ और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सीमित पहुँच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप रोज़गार वृद्धि के साथ-साथ कामगार वर्ग में रोज़गार असुरक्षा भी बढ़ी है।

औद्योगिक विकास ने बिलासपुर ज़िले में प्रवासन की प्रक्रिया को भी तीव्र किया है। निर्माण परियोजनाओं, औद्योगिक इकाइयों और शहरी सेवाओं के विस्तार ने ग्रामीण क्षेत्रों और पड़ोसी ज़िलों से श्रमिकों को आकर्षित किया है। विशेष रूप से निर्माण और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में मौसमी और चक्रीय प्रवासन सामान्य हो गया है। अनेक श्रमिक अस्थायी रूप से प्रवास करते हुए अपने मूल गाँवों से संबंध

बनाए रखते हैं। यद्यपि प्रवासन आय के अवसर प्रदान करता है, तथापि प्रवासी श्रमिकों को प्रायः खराब आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कल्याणकारी योजनाओं से वंचना और शहरी समाज में हाशियाकरण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

बिलासपुर के कामगार वर्ग का दैनिक जीवन औद्योगिक विकास की अंतर्विरोधी प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है। रेलवे और कुछ बड़े उद्योगों जैसे संगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को अपेक्षाकृत स्थिर रोज़गार, निश्चित मजदूरी और सीमित सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके विपरीत, लघु उद्योगों, निर्माण, परिवहन और असंगठित सेवाओं में कार्यरत अधिकांश श्रमिक लंबे कार्य घंटे, असुरक्षित कार्यस्थल और व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों से जूझते हैं। श्रम कानूनों के कमजोर क्रियान्वयन और प्रभावी विनियमन के अभाव ने इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया है।

औद्योगीकरण ने कामगार वर्ग की पारिवारिक संरचना और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित किया है। प्रवासन और लंबे कार्य घंटों के कारण पारंपरिक पारिवारिक संबंध कमजोर हुए हैं जिससे एकल परिवारों और एकमात्र कमाने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। महिलाओं की मज़दूरी-आधारित रोज़गार में भागीदारी बढ़ी है, विशेषकर निर्माण, घरेलू कार्य और लघु सेवाओं जैसे असंगठित क्षेत्रों में। तथापि, महिला श्रमिकों को अब भी मजदूरी भेदभाव, रोज़गार असुरक्षा और घरेलू दायित्वों के दोहरे बोझ का सामना करना पड़ता है।
बिलासपुर ज़िले में श्रमिक हितों की रक्षा में मज़दूर संघों और श्रम संगठनों की भूमिका सीमित रही है। रेलवे जैसे संगठित क्षेत्रों में कुछ हद तक संघीकरण देखने को मिलता है, किंतु विशाल असंगठित कार्यबल सामूहिक सौदेबाज़ी की व्यवस्था से लगभग बाहर है। मज़बूत श्रम संगठनों के अभाव ने श्रमिकों की बेहतर मजदूरी, सुरक्षित कार्य स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए मोलभाव करने की क्षमता को कमजोर किया है।

समग्र रूप से, बिलासपुर ज़िले में औद्योगीकरण ने कामगार वर्ग के लिए मिश्रित परिणाम उत्पन्न किए हैं। एक ओर इसने रोज़गार के अवसरों का विस्तार किया, आय के स्रोतों में विविधता लाई और शहरी व अवसंरचनात्मक विकास में योगदान दिया है। दूसरी ओर, इसने श्रम प्रवासन, रोज़गार के असंगठित होने और सामाजिक असुरक्षा को भी बढ़ाया है। बिलासपुर का कामगार वर्ग आर्थिक गतिशीलता और निरंतर असुरक्षा, दोनों का अनुभव कर रहा है, जो औद्योगिक विकास की असमान और विरोधाभासी प्रकृति को दर्शाता है।

अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि बिलासपुर ज़िले में सतत औद्योगिक विकास के लिए समावेशी श्रम नीतियाँ, कार्य स्थितियों का प्रभावी विनियमन, सामाजिक सुरक्षा उपायों का विस्तार तथा प्रवासी और असंगठित श्रमिकों के लिए अधिक संरक्षण अनिवार्य है। इन मुद्दों का समाधान किए बिना औद्योगीकरण केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित रह जाएगा, जबकि सामाजिक न्याय और कामगार वर्ग के जीवन-स्तर में वास्तविक सुधार सुनिश्चित नहीं हो पाएगा।

संकल्पनात्मक रूपरेखा :

औद्योगीकरण : औद्योगीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था का कृषि-आधारित उत्पादन प्रणाली से हटकर विनिर्माण, यांत्रिक उत्पादन तथा सेवा-आधारित गतिविधियों की ओर संरचनात्मक रूपांतरण। समाजशास्त्रीय दृष्टि से औद्योगीकरण केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया भी है, जो वर्ग-संबंधों, श्रम-संगठन, प्रवासन प्रतिरूपों तथा पारिवारिक जीवन की संरचना को पुनः परिभाषित करती है। औद्योगीकरण के अंतर्गत तकनीकी प्रगति, पूँजी निवेश, शहरी विस्तार तथा श्रम-संबंधों में परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जिनके परिणामस्वरूप श्रमिक वर्ग का निर्माण एवं विस्तार होता है।
बिलासपुर ज़िले के संदर्भ में औद्योगीकरण का संबंध निर्माण गतिविधियों, परिवहन सेवाओं, ऊर्जा-संबंधित इकाइयों, रेलवे, खनिज-आधारित उद्योगों तथा लघु विनिर्माण उद्योगों के विकास से जुड़ा हुआ है। इन परिवर्तनों के कारण कृषि पर निर्भरता क्रमशः कम हुई है तथा विशेष रूप से श्रमिक वर्ग में मजदूरी-आधारित रोजगार का विस्तार हुआ है।
श्रमिक वर्ग : श्रमिक वर्ग में वे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनकी आजीविका मुख्यतः मजदूरी पर निर्भर होती है तथा जिनके पास उत्पादन के प्रमुख साधन नहीं होते। बिलासपुर ज़िले के संदर्भ में इस वर्ग में कारखाना श्रमिक, निर्माण मज़दूर, परिवहन कर्मी, खनन-संबंधित श्रमिक, रेलवे कर्मचारी, हमाल, मैकेनिक तथा सेवा क्षेत्र के असंगठित श्रमिक शामिल हैं। औद्योगिक विस्तार, रोजगार की असुरक्षा, श्रम प्रवासन तथा कार्य एवं जीवन-स्थितियों में हो रहे परिवर्तन इस वर्ग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

रोजगार प्रतिरूप एवं औद्योगिक वृद्धि:

बिलासपुर ज़िले में औद्योगीकरण के कारण कृषि क्षेत्र से औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों की ओर श्रम-शक्ति का स्पष्ट स्थानांतरण हुआ है, जिससे रोजगार प्रतिरूपों में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं।

तालिका 1 : उत्तरदाताओं का क्षेत्रवार रोजगार वितरण (n = 150)

क्षेत्र	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत (%)
कृषि	42	28.0
विनिर्माण एवं उद्योग	48	32.0
निर्माण	33	22.0
परिवहन एवं सेवाएँ	27	18.0
कुल	**150**	**100**

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि केवल 28 प्रतिशत उत्तरदाता वर्तमान में कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं, जबकि 72 प्रतिशत श्रमिक औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हैं। विनिर्माण एवं औद्योगिक रोजगार (32 प्रतिशत) तथा निर्माण क्षेत्र (22 प्रतिशत) मिलकर कुल रोजगार का आधे से अधिक भाग घेरते हैं। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि औद्योगीकरण के कारण कृषि-आधारित आजीविका से औद्योगिक व्यवसायों की ओर उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। तथापि, इन रोजगारों का अधिकांश भाग असंगठित एवं ठेका-आधारित होने के कारण रोजगार-वृद्धि असमान तथा असुरक्षित स्वरूप की प्रतीत होती है।

प्रवासन एवं श्रमिक वर्ग:

बिलासपुर ज़िले में औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप विशेष रूप से ग्रामीण-शहरी तथा चक्रीय प्रवासन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

तालिका 2 : उत्तरदाताओं की प्रवासन स्थिति (n = 150)

प्रवासन स्थिति	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत (%)
स्थानीय (अप्रवासी)	69	46.0
मौसमी प्रवासी	51	34.0
स्थायी प्रवासी	30	20.0
कुल	**150**	**100**

आँकड़ों के अनुसार 54 प्रतिशत उत्तरदाता प्रवासी श्रमिक हैं, जिससे औद्योगीकरण और श्रम प्रवासन के बीच घनिष्ठ संबंध स्पष्ट होता है। विशेषकर निर्माण तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के बीच मौसमी प्रवासन अधिक पाया जाता है। प्रवासी उत्तरदाताओं ने असुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच तथा कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहने जैसी समस्याओं का उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रवासन अनेक मामलों में स्थायी आजीविका का साधन न बनकर मात्र जीवन-यापन का अस्थायी माध्यम बनकर रह गया है।

कार्य स्थितियाँ एवं श्रम-जीवन:

औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में कार्य स्थितियों में असमानता उत्पन्न हुई है।

तालिका 3 : उत्तरदाताओं के बीच रोज़गार की प्रकृति (n = 150)

रोज़गार श्रेणी	कामगारों की संख्या	प्रतिशत (%)
संगठित एवं स्थायी रोज़गार	33	22.0
ठेका आधारित रोज़गार	62	41.3
असंगठित दैनिक मज़दूरी	55	36.7
कुल	**150**	**100**

केवल 22 प्रतिशत उत्तरदाता संगठित और स्थायी रोज़गार में कार्यरत हैं, जहाँ अपेक्षाकृत स्थिर मजदूरी और सीमित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है। इसके विपरीत, 78 प्रतिशत श्रमिक ठेका या असंगठित रोज़गार में संलग्न हैं जिनकी विशेषताएँ लंबे कार्य घंटे, असुरक्षित कार्य वातावरण, स्वास्थ्य बीमा का अभाव और अनियमित आय हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि औद्योगीकरण ने रोज़गार की संख्या तो बढ़ाई है, किंतु कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा है।

पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रभाव:

औद्योगिक रोज़गार ने कामगार वर्ग की पारिवारिक संरचना और सामाजिक संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है।

तालिका 4 : कामगार वर्ग के परिवारों की संरचना (n = 150)

परिवार का प्रकार	परिवारों की संख्या	प्रतिशत (%)
संयुक्त परिवार	54	36.0
एकल (नाभिकीय) परिवार	74	49.3
एकमात्र कमाने वाला परिवार	22	14.7
कुल	**150**	**100**

एकल परिवारों (49.3 प्रतिशत) और एकमात्र कमाने वाले परिवारों (14.7 प्रतिशत) की प्रधानता प्रवासन, लंबे कार्य घंटों और शहरी जीवन स्थितियों के प्रभाव को दर्शाती है। श्रमिकों के स्थानिक पृथक्करण के कारण पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था में गिरावट आई है। महिलाओं की असंगठित श्रम में भागीदारी बढ़ी है, किंतु उत्तरदाताओं ने मजदूरी असमानता और रोज़गार असुरक्षा की समस्याओं की ओर संकेत किया है, जिससे कामगार परिवारों में लैंगिक असुरक्षाएँ और सुदृढ़ होती हैं।

मज़दूर संघ एवं श्रम संगठन

बिलासपुर ज़िले में श्रमिक अधिकारों की रक्षा में मज़दूर संघों की भूमिका सीमित रही है।

तालिका 5 : उत्तरदाताओं में मज़दूर संघ सदस्यता (n = 150)

संघीय स्थिति	कामगारों की संख्या	प्रतिशत (%)
संघ सदस्य	36	24.0
असंघटित श्रमिक	114	76.0
कुल	**150**	**100**

केवल 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मज़दूर संघ की सदस्यता होने की जानकारी दी, जो मुख्यतः रेलवे जैसे संगठित क्षेत्रों से संबंधित हैं। शेष 76 प्रतिशत असंगठित और ठेका श्रमिक संघीय संरक्षण से बाहर हैं। संगठन के इस अभाव के कारण सामूहिक सौदेबाज़ी कमजोर हुई है, श्रम कानूनों का क्रियान्वयन प्रभावी नहीं हो पा रहा है और श्रमिक शोषण की स्थिति बनी हुई है।

150 कामगार वर्ग के उत्तरदाताओं (n = 150) से प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिलासपुर ज़िले में औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप रोज़गार की मात्रात्मक वृद्धि तो हुई है, किंतु श्रम-जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। यद्यपि औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों ने बड़ी संख्या में श्रमिकों को समाहित किया है, फिर भी असंगठित रोज़गार का प्रभुत्व, प्रवासन पर अत्यधिक निर्भरता, कमजोर श्रम संगठन और असुरक्षित कार्य स्थितियाँ गहरी संरचनात्मक असमानताओं को उजागर करती हैं इस प्रकार, औद्योगीकरण ने एक ओर आर्थिक अवसर उत्पन्न किए हैं, वहीं दूसरी ओर कामगार वर्ग की सामाजिक और आर्थिक असुरक्षाओं को भी तीव्र किया है।

निष्कर्ष:

बिलासपुर ज़िले में औद्योगीकरण ने कामगार वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को गहराई से पुनःआकार दिया है। औद्योगिक और सेवा गतिविधियों के विस्तार ने नए रोज़गार अवसर सृजित किए और आर्थिक विकास को गति दी, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक पारंपरिक कृषि से बाहर आए। इसके साथ ही इस प्रक्रिया ने श्रम प्रवासन को तीव्र किया, असंगठित और ठेका आधारित रोज़गार पर निर्भरता बढ़ाई तथा श्रमिकों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को व्यापक किया है। जहाँ कामगार वर्ग के एक हिस्से ने आय में सुधार और सीमित सामाजिक उन्नयन का अनुभव किया है, वहीं एक बड़ा वर्ग आज भी रोज़गार असुरक्षा, खराब कार्य स्थितियों और अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा से जूझ रहा है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि बिलासपुर में औद्योगीकरण को सतत और न्यायसंगत परिणाम देने के लिए समावेशी श्रम नीतियाँ, कार्य स्थितियों का प्रभावी विनियमन एवं क्रियान्वयन, मज़दूर संघों की सुदृढ़ भूमिका तथा स्थानीय और प्रवासी, दोनों प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने वाली व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएँ अनिवार्य हैं।

संदर्भ:

1. *Allen, R. C. (2009). The British Industrial Revolution in global perspective. Cambridge University Press.*
2. *Bhaskar, M. (1989). Press and working class consciousness in developing societies: A case study of an Indian state, Kerala. Gian Pub. House.*
3. *Boyd, M. (1989). Family and personal networks in international migration: Recent developments and new agendas. International Migration Review, 23(3), 638–670.*
4. *Carling, J. (2002). Migration in the age of involuntary immobility: Theoretical reflections and Cape Verdean experiences. Journal of Ethnic and Migration Studies, 28(1), 5–42.*
5. *Engels, F. (1845). The condition of the working class in England. (Multiple editions available).*
6. *Freund, B. (1995). Insiders and outsiders: The Indian working class of Durban, 1910-1990. Heinemann.*
7. *Hatton, T. J., & Williamson, P. J. (2005). Global migration and the world economy: Two centuries of policy and performance. MIT Press.*
8. *International Labour Organization. (n.d.). A reflection on the future of work and society.*
9. *Jones, E. L. (1988). Growth recurring: Economic change in world history. Oxford University Press.*
10. *Kapás, J. (2008). Industrial revolutions and the evolution of the firm's organization: An historical perspective. Journal of Innovation Economics & Management, 2(2), 15–33. https://doi.org/10.3917/jie.002.0015*
11. *Lambert, R. D. (1987). The transformation of an Indian labour market: The case of Pune. Orient Longman Limited.*
12. *Landes, D. S. (1969). The unbound Prometheus: Technological change and industrial development in Western Europe from 1750 to the present. Cambridge University Press.*
13. *Lopez-Sanders, L. (Forthcoming). The manufacturing of job displacement: How racial capitalism drives immigrant and gender inequality in the labor market. New York University Press.*
14. *Min, J., Kim, Y., Lee, S., Jang, T.-W., Kim, I., & Song, J. (2019). The fourth industrial revolution and its impact on occupational health and safety, worker's compensation and labor conditions. Safety and Health at Work, 10(4), 384-385. doi.org*
15. *Mokyr, J. (2009). The enlightened economy: An economic history of Britain 1700-1850. Yale University Press.*

16. *Sinha, S. (2013). The making of the Madras working class. LeftWord Books.*
17. *Terkel, S. (1974). Working: People talk about what they do all day and how they feel about what they do. Pantheon Books.*